के अनुसार, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की और नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी) की बकाया राशियां 2572.83 करोड़ रुपये (ऊर्जा देयताओं के सम्बन्ध में 1544.62 करोड़ रुपये—विलम्बित भुगतान हेतु प्रभारों के सम्बन्ध में 1028.21 करोड़ रुपये) हैं।

बकाया राशियों की इतनी अधिक मात्रा होने के परिणामस्वरूप कैश की कमी से एन.टी.पी.सी. की चरमराई वित्तीय स्थिति हो गई है। इससे कोयले/गैस की आपूर्ति आदि के लिए एनटीपीसी की अदायगी क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जबकि इस समय एन.टी.पी.सी. द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत की सप्लाई में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, ऐसे राज्य बिजली बोर्डों जिनके द्वारा बहुत समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, के मामले में एन.टी.पी.सी. द्वारा बोर्डों द्वारा किए जा रहे भुगतान के समानुपात सप्लाई विनियमित किया जाना आवश्यक होगा।

बकाया राशियों की वसूली हेतु उठाए गए कदमों में राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य सरकारों से बार बार अनुरोध किया जाना शामिल है। इस मामले में, सम्बन्धित राज्य सरकारों से बारम्बार अनुरोध किए जाने और केन्द्रीय विनियोजन के द्वारा वसूली किए जाने के माध्यम से भी केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता रहा है।

विदेशी फर्म द्वारा देश में विद्युत इकाईयों का नवीकरण करने की पेशकश

1687. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटभाई पटेल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी फर्म ने हाल ही में हमारे देश में विद्युत उत्पादक यूनिटों का नवीकरण करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) ताप विद्युत यूनिटों के नवीकरण हेतु पांच विदेशी फर्मों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं तथा जल-विद्युत यूनिटों के नवीकरण हेतु ग्यारह विदेशी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) इस मामले में संबंधित परियोजना प्राधिकारियों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

विवरण

देश में विद्युत यूनिटों के नवीकरण हेतु विदेशी फर्मों के प्रस्तावों की सूची

क्र. सं०	विदेशी फर्म का नाम	यूनिट का नाम जिसका नवीकरण किया जाना है।
1	2	3
	ताप विद्युत यूनिटें :	
1.	मैसर्स डिटाबी लि. जापान	कोठागुडम "क"
2.	मैसर्स आई.एच.आई. जापान	कोठागुडम "क"

1	2	3
	3. आसिया ब्राउन बोवेरी, जर्मनी (एबीबी)	तलचेर
	4. मैन एनर्जी, जर्मनी	दुर्गापुर
	5. टैक्नोप्रोग एक्सपोर्ट ऑफ रशिया (टीपीई)	नेवेली
	जल विद्युत यूनिटें :	
	1. एबीबी पावर जनरेशन, बदेन, स्विटजरलैण्ड	नेरिय्यामंगलम
	2. हाइड्रोपेवैक्स, स्विटजरलैण्ड	नेरिय्यामंगलम तथा कोरियंगलकुट्टू
	3. जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी, कनाडा	साबरीगिरी
	4. वोइथ, जर्मनी	हीराकुड-एक
	5. सिमन्स, जर्मनी	हीराकुड-एक
	6. बोइथ, जर्मनी (एल एंड टी के माध्यम से)	हीराकुड-दो
	7. ए. ई. जी. जर्मनी	कोयना-1 और 2
	8. नैरपिक, फ्रांस	कोयना-1 और 2
	9. हाइड्रो वैवै, स्विटजरलैण्ड	कोयना-1 और 2
	10. एबीबी, जर्मनी	मचकुंद
	11. वोइथ, जर्मनी	मचकुंद

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उठाए गए घाटों के कारण

1688. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के गत वर्षों में सुचारू रूप से संचालन हेतु 1200 करोड़ रुपये का घाटा वर्ष 1989 में बट्टे खाते डाला था;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1990-91 में घरेलू उपभोक्ता प्रयोग में आने वाली बिजली की कीमतों में 50% वृद्धि भी की गई थी तथा बड़े औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं पर यह वृद्धि 150% तक थी;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को अभी पुनः 470 करोड़ रुपये का नकद घाटा हो चुका है तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत परियोजना के प्रति उसकी 2100 करोड़ रुपये की राशि बकाया के रूप में देय है;